भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6183
उत्तर देने की तारीख 01 अप्रैल, 2026

बिना कवरेज वाले गाँवों में 4जी सैचुरेशन परियोजना

6183. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
श्री शंकर लालवानीः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री तापिर गावः
श्री चिन्तामणि महाराजः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्री नव चरण माझीः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री गोपाल जी ठाकुरः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मोबाइल सम्पर्क सुविधा प्रदान करने के लिए 4जी संतृप्ति परियोजना के अन्तर्गत चिन्हित कवर नहीं किए गए गांवों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा क्या है और कुल संख्या कितनी है, जिसमें विशेषकर उत्तर प्रदेश के हाथरस लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, पालनाडु जिला, पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिला तथा सरगुजा संभाग शामिल हैं;

(ख) उक्त परियोजना के अंतर्गत अब तक स्थापित मोबाइल टावरों की संख्या का ब्यौरा क्या है और हाथरस जिले, दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, सरगुजा संभाग में कितने गांवों में 4जी सेवाएं आरंभ/प्रदान की गई हैं;
(ग) उक्त परियोजना की स्वीकृति से लेकर अब तक इसके कार्यान्वयन हेतु आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त परियोजना विशेषकर शेष ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उसे पूरा करने हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा विशेषकर कच्छ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और सरगुजा संभाग, प्लानाडू जिला और पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित ग्रामीण सुदूर और वन क्षेत्रों, सीमावर्ती और आकांक्षी जिलों में तीव्र सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला-वार क्या कदम उठाए गए हैं;
(च) क्या सरकार के पास सरकारी विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और ग्राम पंचायत भवनों को उच्च गति इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना है;
(छ) उक्त परियोजना के अनुमोदन के पश्चात् इसके कार्यान्वयन हेतु कुल आवंटित एवं जारी निधियों का ब्यौरा और परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है; और
(ज) सरकार द्वारा दूरस्थ, सीमावर्ती एवं आकांक्षी ज़िलों में विशेष रूप से खासकर आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले सहित कम सुविधाओं वाले इलाकों में मोबाइल संपर्क को तीव्र करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ङ) और (ज): सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों और आकांक्षी जिलों सहित देश भर के सेवा से वंचित गांवों को 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 4जी सैचुरेशन परियोजना को अनुमोदित किया है। दिनांक 28.02.2026 तक, इस 4जी सैचुरेशन परियोजना के तहत 14,301 टावर ऑन-एयर किए जा चुके हैं, जिनसे 21,384 गांव कवर किए गए हैं। दिनांक 28.02.2026 तक, 4जी सैचुरेशन परियोजना के तहत कुल 9417.88 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना के अंतर्गत मंजूर मोबाइल टावरों, ऑन-एयर टावरों और कवर किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) की वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है।

हाथरस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र - उत्तर प्रदेश, पालनाडु जिला-आंध्र प्रदेश, पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र -राजस्थान, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिले-मध्य प्रदेश, सरगुजा संभाग-छत्तीसगढ़, दाहोद

और कच्छ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों -गुजरात, में 4जी सैचुरेशन परियोजना की स्थिति डीबीएन की वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है।

(च) और (छ): भारतनेट कार्यक्रम, जिसे डीबीएन के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है, को सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। दिनांक 04.08.2023 को अनुमोदित संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) में भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करने का प्रावधान है, जिसके तहत पांच वर्षों में स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ियों, पंचायत कार्यालयों आदि सहित सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता के साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 1.5 करोड़ 'फाइबर टू द होम' (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं। दिनांक 28.02.2026 तक, भारतनेट परियोजना के तहत कुल वितरित धनराशि 48,372.50 करोड़ रुपये है।

*****